projects in the Western Region, guarding of oil wells and other installations|pipelines by the oil industry's security staff, Gramrakshak Dal, Home Guards and local police at places as in convenient. In Gujarat area, helicopter surveillance of pipelines is also resorted to in areas where patrolling is otherwise not possible owing to difficult terrain and distance involved.

As regards theft of petroleum products from refineries/installations/depots/retail outlets, etc., consolidated data in this regard is not maintained by the oil companies. Since the number of such installations, depots, etc. is over 15,600 throughout the country the effort involved in collection and compilation of the required information for the past three years from the State Governments and Union Territory Administrations besides the oil companies/refineries, will not be commensurate with the purpose sought to be achieved. Nevertheless, suitable security arrangements, exist at refineries|installations|depots of the oil companies.

Supply of gas at concessional rates

1451. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI RAMSINGHBHAI PATALIYABHAI RATHVA-KOLI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that natural gas producing countries are working out gas prices as equivalent to coal; if so, which are these countries and what is the price of natural gas in those countries;

(b) what are the reasons for not supplying the natural gas at concessional price to backward Taluka; and

(c) what are the reasons for which Government do not consider it proper to supply gas at concessional rates from isolated wells?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BRAHM DUTT): (a) There are no fixed international standards for fixing natural gas price and these vary from country to country.

(b) and (c) Concessions have been provided for the consumers in the North-East, in view of the backwardness of the region; and to fall-back users and those getting gas from the fields under development.

आई०एस०आई० चिन्ह के बिना घरेलू गैस के बर्नरों और हाट प्लेटों की बिक्री

1452. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई०एस०आई० मार्क या कोई भी ट्रेड मार्क के बिना अथवा डुप्लीकेट आई०एस०आई० ट्रेड मार्क वाले खाना पकाने की घरेलू गैस के बर्नर और हाट प्लेटों की बाजार में खुले आम बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है और क्या इस संबंध में कोई विसंगति सरकार के ध्यान में आई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) से (ग) जबकि एल०पी०जी० स्टोवों के विनिर्माताओं के लिये आई०एल०आई० प्रमाणन प्राप्त करने के संबंध में उनका कोई सांविधिक दायित्व नहीं होता है, फिर भी एल०पी०जी० के वितरों को निर्देश दिये गए हैं कि वे केवल एल०पी०जी० स्टोवों का स्टाक रखें/बिक्री करें जिन पर आई०एस०आई० का मार्क होता है और उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० के कनेक्शन तभी रीलीज करें जब ऐसा सत्यापन किया

जाए कि उपभोक्ता के पास प्रमाणित स्टोव है।

डबल बाटल कनेक्शन की खरीद पर इंसटालेशन चार्ज

1453. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दो वर्षों से दिल्ली में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के घरेलू गैस वितरक ग्राहकों द्वारा डबल बाटल कनेक्शन खरीदने पर उनसे 5 रुपये इन्सटालेशन चार्ज के रूप में वसूल कर रहे हैं जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के वितरक कोई "इन्सटालेशन चार्ज" वसूल नहीं करते हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वितरकों द्वारा ग्राहकों से वसूल किये गये इन्सटालेशन चार्ज को ग्राहकों को निकट भविष्य में लौटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) जी हां।

(ख) और (घ) एक तेल कम्पनी से दूसरी तेल कम्पनी के परिचालनात्मक और व्यापारिक निर्णयों का भिन्न-भिन्न होना सामान्य है।

(ग) जी, नहीं।

खाना पकाने की घरेलू गैस की एजेंसिया और उनके द्वारा रिफिल्स की सप्लाई

1454. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में (i) इंडियन आयल कारपोरेशन, (ii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, (iii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा खाना पकाने की घरेलू गैस की कुल कितनी एजेंसियां चलायी जा रही हैं ;

(ख) उसके वितरकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) ग्राहकों को सप्लाई किये जाने हेतु प्रत्येक वितरक के पास कितने रिफिल पंजीकृत कराये गये हैं;

(घ) इस समय कितने रिफिल सप्लाई किये जा रहे हैं और कितने रिफिल की सप्लाई गत छः महीने से बद्ध हैं ;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में गोपनीय जांच करवाने का विचार रखती हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां। दिल्ली में कार्य कर रहे एल०पी०जी० वितरकों की कम्पनीवार संख्या निम्नलिखित है:—

इंडियन आयल कारपोरेशन .	112
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	28
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन .	31
	171